देश में राष्ट्रीय पेयजल योजना

1337. **श्री रामजी लाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में राष्ट्रीय पेयजल योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तथा 28 फरवरी, 1993 तक के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया था और यह लक्ष्य वर्षवार किस सीमा तक हासिल हुआ और इस संबंध में राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त योजना के लिए राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है और 1993-94 के वर्ष के दौरान इस हेतु क्या प्रावधान किया गया है तथा इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) गत तीन वर्षों और 1992-93 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार लक्ष्यों और उपलब्धियों को अनुपत्र-1 में दिए गए विवरण में दर्शाया गया है । [देखिए परिशिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 28] केन्द्र सरकार के स्तर पर जिलावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं । मिनी मिशन जिलों में समग्र लक्ष्यों और उपलब्धियों को अनुपत्र-2 में दर्शाया गया है । [देखिए परिशिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 28]

(ग) गत तीन वर्षों और 1992-93 के दौरान रिलीज की गई राशि के राज्यवार ब्यौरे अनुपत्र-3 में दर्शाए गए हैं । [देखिए परिशिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 28] 1993-94 के लिए राज्यवार आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं :—

— शेष 21.60 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (1991 की गणना के अनुसार) जिसे पेयजल सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं, को पेयजल सुविधाएं मुहैया कराना ।

— मार्च, 1993 तक बकाया 2968 "बिना जल स्रोत" वाले अधिक समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराना ।

— 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से कम पानी वाले आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त गांवों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना ।

— अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देना ।

— 1995 तक गिनीकृमि का उन्मूलन करना ।

— पेयजल में अन्य जैविक और रासायनिक संदूषण को दूर करने के लिए समाधान ढूंढना ।

Performance of Poverty Allegation Programmes

1338. SHRI K. K. BIRLA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the details of the major poverty alleviation programmes under implementation at present with both—physical and financial targets, State-wise;

(b) what has been their performance during 1991-92 and 1992-93; and what are the agencies through which the allocated amount is distributed for more development;

(c) the details of shortcomings noticed in the implementation of these programmes alongwith any evaluation; and

(d) the steps taken to remove these shortcomings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) :(a) and (b) The major poverty alleviation programmes under implementation in the country are (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP) and (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY). The main objective of IRDP is to enable the identified rural poor families to rise above the poverty line. This objective is sought to be achieved by providing income generation assets to the beneficiaries through Government subsidy and bank loan. As regards JRY this programme aims to generate additional gainful employment for the unemployed/underemployed persons both men and women in the rural areas.

Statements giving details of physical and financial targets and achievements under these programmes during 1991-92 and 1992-93 are given in Annexure-I and II respectively. [*see* Appendix CLXVI, Annexure No. 29].

(c) and (d) The Integrated Rural Development Porgramme is constantly monitored and reviewed in consultation with the State Govts. Other organisations like the Programme Evaluation Organisation (PEO), Reserve Bank of India (RBI), the National Bank for Rural Development (NABARD), Institute for Financial Management & Research (IFMR) and many independent studies have been made on this programme. Since, 1986, a process of concurrent evaluation has been initiated by the Ministry involving a large number of reputed research organisations. Three rounds of concurrent evaluation in 1986, 1987 and 1989 have been completed and the fourth round has commenced from September, 1992. Steps are regularly taken to remove the shortcomings brought out by the evaluation reports.

As regards JRY, this programme is also being independently evaluated through reputed and independent research organisations. Based on the evaulation study of JRY made during January to December, 1992, necessary follow up measures are being taken to remove the shortcomings and improve the implementation of the programme.

स्व-रोजगार योजना हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण

1339. **श्री राम जेठमलानी :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षण देने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में ग्रामीण युवा-स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राईसेम) के अंतर्गत प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रस्तावित युवाओं की संख्या क्रमश: 3 लाख तथा 3.50 लाख है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

Setting up of Indo-Japanese Science Council

1340. DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Indo-Japanese Science Council has recently been set up; if so, what are the objectives of the Council;

(b) the names of the personnel of the Council from both the countries; and

(c) the number of meetings of the Council held, so far, and the decisions taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM) :

(a) Sir, such a Council has been formed as an arrangement for facilitating cooperative activities between Indian and Japanese scientists.